<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

**10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने 6 जनवरी को प्रेस सम्मेलन में निम्न प्रेस विज्ञप्ति जारी की**

# 8 जनवरी की राष्ट्रीय हड़ताल की ऐतिहासिक सफलता के लिए श्रमिकों की भरपूर तैयारी, 25 करोड़ से ज्यादा की भागेदारी होगी

केंद्रीय श्रमिक संगठनों की इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एक्टु, एलपीएफ एवं यूटीयूसी तथा विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय स्वतंत्र फेडरेशनों/एसोसिएशनों के द्वारा 30 सितंबर 2019 को आयोजित श्रमिकों के राष्ट्रीय खुले अधिवेशन में एक घोषणापत्र पारित किया गया था जिसके अनुसार विस्तृत कार्यक्रम तय  किए गए थे जो 8 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय आम हड़ताल का स्वरूप लेंगे। (30 सितंबर 2019 के घोषणापत्र की प्रति संलग्न है।)

प्रचार बहुत सफलतपूर्वक किया गया। लगभग सभी राज्यों में संयुक्त कन्वेंशन, औद्योगिक आधाार पर राष्ट्रीय फेडरेशनों की बैठकें, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय कन्वेंशनों, कुछ अन्य राज्यों में पदयात्राएं, जत्था प्रचार आदि भी आयोजित किए गए। इन संयुक्त गतिविधियों के अतिरिक्त, केंद्रीय संगठनों, फेडरेशनों/एसोसिएशनों ने अपनी यूनियनों के द्वारा विस्तृत प्रचार प्रसार भी किया। कई लाखों की गिनती में राज्यों की भाषाओं में मांगों के प्रसार के पैम्फलेट संयुक्त तौर पर भी व यूनियनों ने अपनी पहल पर भी प्रकाशित किए और आम जनता में बांटे गए। यूनियनों द्वारा हड़ताल के नोटिस भी जारी किए गए हैं।

श्रम मंत्री ने जो 2 जनवरी को श्रमिक संगठनों के साथ बैठक की, उसमें श्रमिकों की किसी भी मांग पर कार्यवाही का आश्वासन नहीं मिला। सरकार की मजदूरों के प्रति पूरी तरह से नकारात्मक सोच है जो हमें सरकार की नीतियों और उनके उठाए कदमों से साफ स्पष्ट होती हैं। 4 वर्ष से ऊपर हो गए जब जुलाई 2015 में राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हुआ था। मंत्रियों का समूह जो श्रमिक यूनियनों के 12 सूत्री मांग पत्र पर उनसे वार्ता के लिए बनाया गया था उसकी बैठक अगस्त 2015 में हुई थी। उसके बाद से इस मामले में कोई और बैठक आज तक नहीं हुई। यह स्पष्ट है कि त्रिपक्षीय व द्विपक्षीय वार्ता के प्रति सरकार में नकारात्मक नीति है जो मजदूर संगठनों की राय को अनदेखी करते हुए जबरदस्ती श्रम कानूनों में मालिकपरस्त परिवर्तन तथा कोडिफिकेशन किया जा रहा है, उसमें साफ दिखाई देती है।

सरकार जो घोर आर्थिक संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम है, वह मुनाफा देने वालों सार्वजनिक उद्यमों, प्राकृतिक संसाधनों व अन्य राष्ट्रीय संपदा को बेचने में व्यस्त है जो कि राष्ट्रीय विकास व राष्ट्रीय हित के लिए घातक है।

12 एयरपोर्ट बेचे गए हैं, एयर इंडिया को 100 फीसदी बेचने का निर्णय, तेल क्षेत्र में बीपीसीएल को बेचने का निर्णय, बीएसएनएल व एमटीएनएल का विलयीकरण की घोषणा तथा वीआरएस के नाम

पर 93600 कर्मचारियों को नौकरियों से बाहर किया जाना, रेलवे में निजीकरण के कदम बढ़ाए जा रहे हैं, टेलीकॉम के दर्जनों प्लेटफार्म निजी हाथों में दिए गए हैं, रेलवे उत्पादन यूनिटों को कार्पोरेटाईज करने का निर्णय व 150 के करीब प्राईवेट गाडियां चलाने का निर्णय जो सरकार के रेलवे विभाग द्वारा आम नागरिकों को सेवाएं देने पर कुप्रभाव डालेगा। इसी तरह डिफेंस उत्पादन की 49 इकाइयों को कार्पोरेटाइज करने का सरकारी निर्णय जिसका डिफेन्स यूनियनों ने शानदार हड़ताल करके विरोध किया जो फौरी तौर पर रूका है, बैंकों का विलयीकरण कर्मचारियों व अफसरों की यूनियनों के संयुक्त विरोध के बावजूद बढ़ाया गया, रेलवे, डिफेंस, फार्मा, रिटेल ट्रेड, पशुपालन, सिक्योरिटी सर्विसेज आदि के साथ–साथ अब कोयला क्षेत्र में भी 100 फीसदी विदेशी पूंजी का निर्णय लिया गया जिसके विरोध में यूनियनों ने सफल हड़ताल की। उर्जा के क्षेत्र में तथा रोडवेज में तथा इंशोरेंस सेक्टर में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसानों व खेत मजदूरों के 175 से ज्यादा संगठनों के प्लेटफार्म से 29–30 नवंबर 2019 में सम्मेलन आयोजित कर श्रमिकों की हड़ताल को समर्थन दिया है और उन्होंने अपनी मांगों को जोड़ते हुए 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का नारा दिया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान है कि 60 के लगभग छात्र संगठनों व विश्वविद्यालय छात्र संघों के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस सम्मेलन कर छात्रों की शिक्षा फीस वृद्धि व शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में आंदोलन को देशभर में तेज करते हुए 8 जनवरी को श्रमिकों की हड़ताल के साथ एकजुटता एक्शन का भी निर्णय हुआ है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों पर हमले किए जा रहे हैं, और कल ही रात बर्बरता पूर्ण हमला जेएनयू के छात्रों–शिक्षकों पर किया गया, हम श्रमिक संगठन इसकी तीव्र निंदा करते हुए देश भर के छात्रों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं।

हमारी उम्मीद है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग 8 जनवरी की इस आम हड़ताल में शामिल होंगे और सरकार की मजदूर विरोधी, जन विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरूद्ध इस हड़ताल के बाद संघर्ष और तेज किए जाएंगे।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| इंटक | एटक | एचएमएस | सीटू | एआईयूटीयूसी |
| टीयूसीसी | सेवा | एक्टु | एलपीएफ | यूटीयूसी |